नईदुनिया

फ्रांस के साथ एमओयू से प्रदेश की संस्कृति को मिलेगा वैश्विक मंचः डॉ. यादव

मध्यप्रदेश बनेगा भारत-फ्रांस सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग का नया केंद्र

भोपाल(काप्र)।

फ्रांस और मध्यप्रदेश के बीच संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष मुख्यमंत्री निवास, समत्व में एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह मध्यप्रदेश को भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक एवं पर्यटन सहयोग का नया केंद्र बनाएगा।

इस ऐतिहासिक एमओयू पर भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थिएरी मथौ, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिव शेखर शुक्ला और अलायंस फ्रांसेज डी भोपाल के अध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता अगले तीन वर्षों के लिए वैध होगा और आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत और फ्रांस के साथ सम्बन्ध हमेशा से अच्छे रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फ्रांस दौरे के बाद यह और प्रगाढ़ हुए है। मध्यप्रदेश फ्रांस के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के लिए भी तत्पर है। उनकी आगामी माह फ्रांस यात्रा प्रस्तावित है। भारत और फ्रांस के बीच औद्योगिक विकास की दृष्टि से, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन मध्यप्रदेश को न केवल देश की सांस्कृतिक राजधानी बल्कि एक प्रगतिशील, वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी दूरदृष्टि को साकार करता है। प्रदेश के कलाकारों को वैश्विक मंच मिलेगा और फ्रांस तथा यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थिएरी मथौ ने इस साझेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, हमें मध्यप्रदेश सरकार के साथ इस महत्वपूर्ण सहयोग को स्थापित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। फ्रांस मुख्य रूप से पर्यटन, सुरक्षा, पर्यावरण और शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य करता है। यह एमओयू दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे कला, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।

एमओयू के तहत प्रमुख रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयुक्त आयोजन किया जाएगा, जिसमें कला उत्सव, संगीत, नृत्य, प्रदर्शनियां, फिल्म स्क्रीनिंग, खानपान और संस्कृति से जुड़े अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। प्रतिवर्ष एक समर्पित इंडो-फ्रेंच सांस्कृतिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की पर्यटन प्रचार सामग्री का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया जाएगा और फ्रांसीसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र के अधिकारियों और गाइड्स को फ्रेंच भाषा एवं संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

यह समझौता प्रदेश की सांस्कृतिक रणनीति को बल देगा और स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों, छात्रों तथा सांस्कृतिक संगठनों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा, जिससे मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग राघवेंद्र कुमार सिंह, फ्रांस के काउंसिल जनरल जीन-मार्क सेरे-शार्ले, फ्रांसीसी दूतावास के राजनीतिक परामर्शदाता, शाद जॉयनाल आबेदीन और अलायंस फ्रांसेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

नौ नगरीय निकायों में एक-एक पार्षद के उप निर्वाचन हेतु मतदान 7 जुलाई को

भोपाल(काप्र)।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 नगरीय निकायों में एक-एक पार्षद के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उप निर्वाचन के लिये मतदान 7 जुलाई 2025 को होगा।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 16 जून से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 23 जून तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 जून है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जायेगा। मतदान 7 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। नगर पालिका परिषद बैरसिया के वार्ड 7, नगरपालिका परिषद सिवनी के वार्ड 11, नगर परिषद सांवेर के वार्ड 7, गौतमपुरा के वार्ड 15, ककरहटी के वार्ड 13, बिछिया के वार्ड 13, खांड के वार्ड 8, न्यूटन चिखली के वार्ड 4 और नगरपरिषद भीकनगाँव के वार्ड 5 में पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन होगा।

श्रम मंत्री पटेल से महाराष्ट्र के अधिकारियों ने की भेंट, फील्ड विजिट में देखा ग्राउंड इम्पैक्ट

सिपरी सॉफ्टवेयर से प्रभावित हुआ महाराष्ट्र का दल

भोपाल (काप्र)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से महाराष्ट्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के छह सदस्यीय दल ने शुक्रवार को उनके शासकीय निवास पर मुलाकात की।

इस अवसर पर वर्षा जल के संचयन और भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने इस दौरान मध्यप्रदेश में वर्षा जल और भूजल प्रबंधन को लेकर किए जा रहे कार्यों और नवाचारों की सराहना की। खासतौर पर दल ने जल गंगा संवर्धन अभियान और सिपरी सॉफ्टवेयर की प्रशंसा की। इस अवसर पर मनरेगा आयुक्त-संचालक वाटरशेड मिशन अवि प्रसाद, महाराष्ट्र सरकार के वाटरशेड विभाग के अतिरिक्त मुख्य

कार्यपालन अधिकारी कमलाकर रणदिवे, अवर सचिव मृदा एवं संरक्षण विभाग देवेन्द्र भामरे, प्रकाश पाटिल, क्षेत्रीय जल संरक्षण अधिकारी दिलीप निपाने, जीआईएस विशेषज्ञ अमोल विधाते और असिस्टेंट इंजी.अविनाश देवपारे शामिल रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्यप्रदेश मनरेगा परिषद द्वारा किए गए नवाचारों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का यह छह सदस्यीय दल 12 जून को दो दिवसीय दौरे पर भोपाल आया। दल के सदस्यों ने फील्ड में जाकर सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित किए गए खेत तालाब और अमृत सरोवरों के निर्माण स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने सिपरी सॉफ्टवेयर के कार्य को गहराई से देखा और उसकी तकनीकी कार्यप्रणाली की सराहना की। यह पहला अवसर है जब मध्यप्रदेश में सॉफ्टवेयर की मदद से वैज्ञानिक पद्धति से खेत तालाब और अमृत सरोवरों के निर्माण स्थलों का चयन किया गया।

राजधानी आगमन के पश्चात दल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी और मनरेगा आयुक्त-संचालक वाटरशेड मिशन अवि प्रसाद से पृथक से भेंट कर विस्तृत चर्चा की। पहले दिन 12 जून को अधिकारियों ने भोपाल जिले की जनपद पंचायत बैरसिया की ग्राम पंचायत गुनगा एवं जैतपुर का भ्रमण किया, जहां उन्होंने सिपरी सॉफ्टवेयर से चिन्हित खेत तालाब और अमृत सरोवरों के निर्माण स्थल देखे। इस दौरान उन्होंने हितग्रहियों से चर्चा भी की। शुक्रवार को दल ने रायसेन जिले के सांची विकासखंड का भ्रमण किया और वहां भी सिपरी सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली को देखा व आवश्यक जानकारियां प्राप्त कीं।

मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर में श्रमिकों की मृत्यु पर किया दुःख व्यक्त

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आए 3 श्रमिकों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने हृदय विदारक घटना में घायल तीन अन्य श्रमिकों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। यह दुर्घटना शुक्रवार को एक मैरिज गार्डन में हुई। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। डॉ. यादव ने दुर्घटना में दिवंगत व्यक्तियों के परिजन को दो-दो लाख रुपए और घायल श्रमिकों के समुचित उपचार के लिए 50- 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह ने भी शुक्रवार को नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में मैरिज गार्डन में बिजली के करेंट लगने से 3 श्रमिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

जल संरक्षण अभियान में बनी लक्ष्य से काफी अधिक जल संरचनाएं

भोपाल(काप्र)।

मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के संकल्प के लिये जन-सहभागिता जुटाने में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध हुआ है। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून, 2025 तक संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नदियों, जल स्त्रोतों और वेटलैंड्स का संरक्षण तथा पुनर्जीवन सुनिश्चित करना है।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी नवीनतम राज्य स्तरीय प्रदर्शन डैशबोर्ड के आकलन के अनुसार खंडवा मध्यप्रदेश में पहले स्थान पर है। इससे पूर्व केन्द्रीय एजेंसी ने जल संरक्षण कार्यों के लिए खंडवा को देश का शीर्ष जिला घोषित किया है। इस सूची में मध्यप्रदेश को चौथे स्थान मिला है। खेत-तालाब निर्माण का लक्ष्य 77,940 तय किया गया था, लेकिन प्रदेश में 79,815 खेत-तालाबों का निर्माण हो रहा है, जो शत प्रतिशत से भी अधिक है। अभियान की अवधि में प्रतिदिन औसतन 1,078 खेत-तालाबों के निर्माण का प्रारंभ किया जा रहा है। डगवेल रिचार्ज संरचनाओं के लिये 1,03,900 के लक्ष्य में से 1,00,321 संरचनाओं का निर्माण जारी है, जो लक्ष्य का 96.56 प्रतिशत है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,355 डगवेल निर्माण शुरू किया जा रहा है। अमृत सरोवर लक्ष्य 992 के मुकाबले 1,254 निर्मित किये जा रहे हैं। मायभारत पोर्टल पर जलदूत पंजीयन का लक्ष्य 1,62,400 तय किया गया था, जबकि 2,30,749 स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया जा चुका है जो लक्ष्य काफी अधिक है।

- प्रदेश को बड़ी सफलता, खंडवा बना देश-प्रदेश का टॉप जिला
- मध्यप्रदेश देश में चौथे नंबर पर, जलदूत पंजीयन का लक्ष्य 1,62,400 और बने 2,30,749

राज्य सरकार ने पाँच प्रमुख क्षेत्रों— पुराने एनआरएम कार्य, खेत-तालाब, डगवेल, अमृत सरोवर और मायभारत पंजीयन — पर आधारित 100 अंकों की रैंकिंग प्रणाली लागू की है। इस आधार पर खंडवा जिला 71.09 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। खेत-तालाब निर्माण, डगवेल रिचार्ज और अमृत सरोवर की शुरुआत में खंडवा का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा। रायसेन (60.85 अंक), बालाघाट (59.52 अंक) और बुरहानपुर (55.85 अंक) क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। प्रदेश के अधिकांश जिलों ने अमृत सरोवर और मायभारत श्रेणियों में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं।

एम्स में अंतर्राष्ट्रीय स्कल बेस सर्जरी कार्यशाला

भोपाल (काप्र)।

एम्स के न्यूरोसर्जरी एवं एनाटॉमी विभाग द्वारा भोपाल की न्यूरो एसोसिएशन के सहयोग से आईएसबीएम स्कल बेस कोर्स का आयोजन किया गया है, जो न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और प्रमुख कार्यक्रम है।

यह तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस 13 से 15 जून तक एम्स परिसर में आयोजित की गई है, जिसकी शुरुआत आज, हैंड्स-ऑन स्कल बेस सर्जरी कार्यशाला के साथ हुई। कार्यशाला में कैडेवर आधारित अभ्यास के माध्यम से एंडोस्कोपिक स्कल बेस सर्जरी तकनीकों और माइक्रोवैस्कुलर एनास्टोमोसिस की उन्नत विधियों पर फोकस किया गया। कार्यशाला में देश-विदेश के वरिष्ठ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, न्यूरोसर्जनों तथा प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। दिन की शुरुआत विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा लाइव डेमोंस्ट्रेशन से हुई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अभ्यास सत्रों में भाग लिया। यह कार्यशाला 100 से अधिक प्रतिभागियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई, जिसमें प्रैक्टिसिंग न्यूरोसर्जन और रेजिडेंट्स दोनों शामिल थे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह ने कहा, एम्स को इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी पर गर्व है। यह न केवल मध्य भारत की अकादमिक क्षमता को सुदृढ़ करता है, बल्कि न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 14 जून को किया जाएगा, जिसके पश्चात 14 व 15 जून को एक गहन शिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञ व्याख्यान, केस डिस्कशन, सर्जिकल वीडियो डेमोंस्ट्रेशन एवं कैडेवरिक डिसेक्शन सत्र शामिल होंगे। इस कोर्स में 200 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

निगम अमले ने पांच अवैध दुकानों को कराया बंद

नगर निगम द्वारा शहर में बिना लायसेंस के अवैध रूप से मांस-मटन विक्रय करने वाले संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है। निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में मांस-मटन विक्रय करने वालों की दुकानों का निरीक्षण तथा लायसेंस आदि की जांच निरंतर की जा रही है। निगम के अमले ने शुक्रवार को जोन क्र. 20 के अंतर्गत एयरपोर्ट के आसपास वार्ड क्र. 02 के सी.टी.ओ, बैरागढ़ आदि क्षेत्रों में संचालित मांस-मटन की दुकानों का निरीक्षण किया और अवैध रूप से संचालित 5 मांस-मटन की दुकानों को बंद कराने की कार्यवाही की। उक्त कार्यवाही निगम के जोन क्र. 20 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, वार्ड प्रभारी व अन्य अमले द्वारा की गई।

हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने में नहीं हो कोई असुविधाः राजपूत

भोपाल(काप्र)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को प्रति माह लगभग 2 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सभी 27 हजार 944 उचित मूल्य दुकानों में पीओएस मशीन स्थापित की जा चुकी हैं। श्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उचित मूल्य दुकानों में परिवार के

पात्र हितग्राहियों को प्रति माह 2.90 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न का हो रहा वितरण

किसी भी सदस्य द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन/ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकता है। अशक्त एवं दिव्यांगजनों के लिये नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत यह लोग जिस व्यक्ति को नामांकित कर देते हैं, उन्हें खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। राशन वितरण की सूचना हितग्राही को एसएमएस के माध्यम से भी देने का प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 653 उचित मूल्य दुकानें शेडो एरिया में हैं, यहां पर समग्र परिवार आईडी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है।

स्पेशल खबर राजधानी में अमृत हरित महाअभियान पर कार्यशाला...

नगरीय क्षेत्रों को नगर वन से पर्यावरण के अनुकूल बनाएं : शुक्ला

भोपाल(काप्र)।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने कहा है कि बढ़ती आबादी के दबाव के कारण शहरों का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि जन भागीदारी से हम शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ायें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पौधरोपण के साथ-साथ हम पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में अमृत हरित महा अभियान पर केन्द्रित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण जुड़ी गतिविधियों और पहल का प्रसार करना है। कार्यशाला में समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री शुक्ला ने कहा कि आगामी बारिश के मौसम के दौरान जिन चिन्हित स्थानों पर पौधरोपण होना है, वहां व्यापक स्तर पर तैयारी की जाये। श्री शुक्ला ने कहा कि शासकीय भवन परिसर, कॉलेज एवं स्कूल परिसर के आस-पास पौधरोपण किया जाये। उन्होंने कहा कि नगरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20 से 25 प्रतिशत भाग समृद्ध हरित क्षेत्र होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से जिन पेड़ों को आस्था के साथ लगाया जाता रहा है, हम उनको स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ज्यादा संख्या में लगा सकते हैं। इनमें आम, जामुन, पीपल, नीम इत्यादि हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत किये जाने की भी पहल की जाना चाहिए।

एक करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम

कार्यशाला में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि वर्षा काल के दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापक पौधरोपण और वृक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शत-प्रतिशत जनभागीदारी से सफल हो सकती है। आयुक्त ने कहा कि पौधरोपण के साथ उनकी सुरक्षा से जुड़ी 3 वर्ष की कार्य योजना बनाये जाना भी जरूरी है। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक नगर परिषद में एक लाख, नगर पालिका में 5 लाख और नगर निगम में 15 से 20 लाख पौधरोपण की योजना तैयार की जाये। औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा करते हुए आयुक्त ने कहा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में वर्षा काल के इस सीजन में 11 लाख पौधरोपण की योजना तैयार की गई है। इसी तरह की योजना मंडीदीप सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी बनाई जा रही है। आयुक्त ने कहा कि हमें अमृत मित्र तैयार करना होंगे, जो इस कार्य में सहयोग करेंगे।

विषय विशेषज्ञों ने दी जानकारी

कार्यशाला में अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े, आईआईएफएम के डॉ. योगेश दुबे ने शहरी अधोसंरचना में नीली-हरी अवसंरचना का प्रबंधन, एप्को के रामरतन ने जलवायु परिवर्तन, एसपीए भोपाल के सौरभ पोपली ने शहरी स्थल पर हरित प्रणाली, अपर आयुक्त सुश्री टीना यादव ने पर्यावरण संरक्षण संबंधित कानून और प्रमुख अभियंता प्रदीप मिश्रा ने नगर वनों के विकास की जानकारी दी। कार्यशाला में दिव्यांग पार्क और छिंदवाड़ा में आधुनिक पार्क पर केन्द्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। रवीन्द्र भवन परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का बड़ी संख्या में नागरिकों ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में खाद, बीज, उन्नत किस्म के पौधे, कृषि और उद्यानिकी के लिये उपयोगी यंत्रों का विक्रय एवं प्रदर्शन किया गया।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com